International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628 Print ISSN: 2664-861X
Received: 15-05-2023, Accepted: 14-06-2023, Published: 29-06-2023
Volume 5, Issue 2, 2023, Page No. 34-36

भारत में संपोषित विकास की चुनौतियांः एक विवेचन

डॉ. पुष्पा देवांगन[1], डॉ. बलभद्र प्रसाद देवांगन[2]
[1] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, के. पी. महाविद्यालय, बंधापाली सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत
[2] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, अशोका महाविद्यालय, उम्मेदपुर, सारंगढ, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
भारत जैसे विकासशील राष्ट्र ने अपने स्थायी/संपोषित विकास हेतु अनेक चुनौतियों एवं मुद्दों को अपनी कार्य योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों में शामिल किया है। परन्तु स्थायी एवं संपोषित विकास हेतु वर्तमान विकास योजनाओं में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो ही वरन भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त साधन एवं संसाधन उपलब्ध हो सके। साथ ही आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ऊर्जा, खाद्यान्न सुरक्षा, जल आदि के उपभोग में प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता, वन्य, पारिस्थितिकीय तंत्र आदि को क्षति न पहुंचे और न ही इनका क्षरण हो। साथ ही इनके संरक्षण एवं संवर्धन को भी प्राथमिक एवं मुख्य मुद्दों के रूप में शामिल किये जाए। पारम्परिक ऊर्जा के संसाधनों के दोहन की अपेक्षा गैर पारम्परिक अथवा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग एवं उपभोग पर जोर दिया जाना आवश्यक है।

मूल शब्दः संपोषित विकास, मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता, संरक्षण एवं संवर्धन, नगरीकरण

भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जिसने आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, कृषि, सेवा व सैन्य क्षेत्रों में असाधारण रूप से प्रगति की है। भारत अपने विकास लक्ष्यों को पाने हेतु सतत् प्रयत्नशील रहा है। आर्थिक, तकनीकी एवं शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत ने अधिक सशक्त स्थिति बनायी है। सभी संसाधनों पर नियंत्रण एवं दोहन कर अधिक से अधिक आर्थिक विकास की ओर अग्रसित है फिर चाहे वह मानवीय संसाधन हो, आर्थिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में विकासात्मक तत्व दृष्टिगोचर हो रहे हैं, देश की लगभग डेढ़ सौ करोड़ की आबादी इस विकास से अछूती नही है, चाहे वह जनजातीय, ग्रामीण या नगरीय समुदाय ही क्यों न हो विकास हर क्षेत्र में किया जा रहा है। परन्तु यह विकास कहीं न कहीं असंतुलित दृष्टिगोचर होता है। देश के अनेक क्षेत्रों में जैसे जनजातीय ग्रामीण एवं छोटे कस्बाई क्षेत्रों में विकास के तत्व तो दिखाई देते है परन्तु पर्याप्त या संपूर्ण विकास की कल्पना करना अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है। जहां एक ओर नवीन तकनीकी विकास के फलस्वरूप सूचना एवं संचार माध्यमों के विकास से देश की जनसंख्या अत्यधिक सरल व सहज जीवन–यापन भी कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश की एक बड़ी आबादी इन नवीन तकनीकी, सूचना, संचार एवं विकास के विभिन्न आयामों से दूर है तथा इसके संपूर्ण विकास की परिकल्पना कर पाना कठिन है। क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी अभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ है। देश में आर्थिक सामाजिक विकास को लेकर जो भी नीतियां बनायी जाती है वह केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित व केन्द्रित होती है, जबकि अधिकांश ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों एवं कस्बों में निवास करने वाली आबादी इन विकास नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती और उपेक्षित ही रह जाती है। शहरी एवं ग्रामीण सूदरवर्ती क्षेत्रों का यह असंतुलन भारत जैसे विकासशील एवं प्रगतिशील राष्ट्र का विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए एक चुनौती है और कही ना कहीं यह एक चेतावनी भी है, कि जब देश का एक बड़ा हिस्सा उपेक्षित, साधनहीन तथा अनेक आयामों में विकास की परिधि से बाहर है तो किन आधारों पर भारत एक विकसित राष्ट्र बन पायेगा।

स्थायी/संपोषित विकास की अवधारणा

स्थायी अथवा संपोषित विकास (Sustainable Development) विकास की वह अवधारणा है जिसमें विकास की नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मानव की न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो वरन अनन्त काल तक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। स्थायी/संपोषित विकास ऐसा विकास है, जो विश्व के समस्त देशों के सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ पर्यावरणीय, मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग एवं संरक्षण पर बल देता है और साथ ही ऐसे तंत्र/पद्धति/तकनीक के विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देता है जिसमें तीव्र गति से उपयोग/उपभोग होने वाले संसाधनों का पुर्नउत्पादन किया जा सके, ताकि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। स्थायी विकास की अवधारणा अपने अन्तर्गत विचारों एवं धारणाओं के एक विस्तृत क्षेत्र को शामिल करता है। यह अवधारणा विकासशील देशों को विकास की सीमा निर्धारित करते हुए पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के सीमित दोहन व उपयोग के साथ ही इन्हें संरक्षित व सवंर्धित करने हेतु प्रोत्साहित करती है। विश्व के समस्त देशों के सामने एक गंभीर चिंता यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम अंधाधुन दोहन के फलस्वरूप भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनो को किस तरह बचाए रखा जाए। दुनियाभर की अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सरकारें, पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवि, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर इन समस्याओं पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही इससे निपटने एवं स्थायी विकास हेतु मार्ग खोजने का प्रयास कर रहे हैं।

स्थायी/संपोषित विकास अवधारणा की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

1972 में ''मानवीय पर्यावरण'' पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से ही भारत में गरीबी हटाने की रणनीति के साथ स्थायी विकास की अवधारणा की शुरूआत हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं मानव विकास को एक साथ जोड़ते हुए स्थायी विकास के लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रियो डी जेनेरियो में आयोजित ''अर्थ समिट (Earth Summit) 2012''

जिसे Rio+20 या Rio 2012 कहा गया जिसमें निर्देशित स्थायी विकास को देश की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीति एवं कार्य सूची/कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया और इसके साथ ही भारत सरकार ने दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए स्थायी विकास को प्रभावशील ढंग से लागू किया। 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में ''एजेण्डा 21'' को प्रस्तुत किया गया, जिसमें 21वी सदी में सभी राष्ट्रों के स्थायी/संपोषित विकास के लिए कार्य योजना (Blue Print) को विस्तार से प्रदर्शित किया गया और साथ ही स्थायी विकास प्राप्त करने के लिए नीति निर्माण में व्यापक जनभागीदारी को मूलभूत आधार मानते हुए सभी राष्ट्रों से इसे अपनाने व लागू करने की अपील की गयी जिस पर 178 राष्ट्रो ने समर्थन देते हुए अपने राष्ट्र की नीतियों एवं कार्यक्रमों में इसे शामिल करने पर अभिमत दिए। स्थायी विकास में उपरोक्त तीनों भागों के विकास में यह आवश्यक है कि पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ही सामाजिक एवं आर्थिक विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही लक्ष्य प्राप्ति हेतु सूचना, एकता और सहभागिता के परस्पर आश्रित आधारों को समस्त विकास प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए।

स्थायी/संपोषित विकास एवं भारत

दी युनाइटेड नेशनस् कनवेन्शन टू कम्बेट डिसर्टीफिकेशन (यू.एन. सी.सी.डी.) कनवेन्शन 1997 में सभी सदस्य देशों ने मरूस्थलीकरण एवं सूखा की समस्या से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार की साथ ही गरीबी के निर्मूलन को मुख्य विषय के रूप में लिया गया। जिसमें वनों की कमी, भू–क्षरण, भूमि कटाव एवं सूखा से भूमि का बचाव किया जाना महत्वपूर्ण माना गया। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया जो कि 2004 में लागू किया गया। जिसके प्रभाव से संवैधानिक रूप से विकेन्द्रित त्रि–स्तरीय संस्थात्मक संरचना का निर्माण किया गया जिसमें–

1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (राष्ट्रीय स्तर पर) (NBA)
2. राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) (प्रदेश स्तर पर)
3. जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMCs) (क्षेत्रीय स्तर पर)

भारत ने ''युनाइटेड नेशनस् फ्रेमवर्क कनवेशन ऑन क्लाइमेट चेन्ज'' (UNFCCC) पर 10 जून 1992 को हस्ताक्षर किए जिसे ''क्योटो प्रोटोकॉल'' (Kyoto Protocol) 2002 के रूप में स्वीकार किया गया, जिसके आलोक में भारत ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन पर रणनीति (NAPCC) बनायी। इस राष्ट्रीय कार्य योजना के आठ मुद्दे है, जो कि स्थायी जैविक विकास पर आधारित है। ''नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी'' (NEP) 2006 भी स्थायी विकास की भावना से ओतप्रोत है। इस राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अनुसार केवल वही विकास स्थायी/संपोषित विकास है जो कि पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किया जाए। भारतीय वन्य अधिनियम 1927 भी वन्य संरक्षण एवं इसके संवर्धन हेतु प्रभावी है। भारत शासन ने ऊर्जा संवर्धन अधिनियम 2001 के तारतम्य में ''ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसिएन्सी'' (BEE) की स्थापना मार्च 2002 में की। जिसका उद्देश्य विकास योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करना है। ऊर्जा संवर्धन अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनो से प्राप्त ऊर्जा की तीव्रता एवं उपयोग में कमी लाना एवं ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनो की खोज करना है।

भारत में स्थायी/संपोषित विकास की चुनौतियां

1. आर्थिक एवं सामाजिक विकास की चुनौतियांः इससे संबंधित समस्याएं निम्न प्रकार है –

(अ) गरीबीः भारत में 2005 में गरीबी रेखा दर 37.2 प्रतिशत थी जो 2012 में घटकर 21.9 प्रतिशत पर आ गई। भारत विश्व की तीव्र विकास वाली अर्थव्यवस्था है जिसकी जी.डी.पी. वृद्धि दर लगभग 9 प्रतिशत है। इसके पश्चात् भी भारत में गरीबी व्याप्त है। जिसमें लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या अधिक है। जो कि स्वच्छ जल, भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से अभावग्रस्त है। भारत में गरीबी के 2009–10 के आंकड़ो के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर 6.53 प्रतिशत है, 50 प्रतिशत भारतीयों के पास उपयुक्त आवास नहीं है। 35 प्रतिशत परिवारों के पास स्वच्छ जल के स्त्रोतो का अभाव है। 85 प्रतिशत ग्रामों में हाई स्कूल नहीं है और लगभग 40 प्रतिशत ग्रामों में शहरों से जोड़ने वाली अच्छी सड़कें नहीं है। कमजोर अधौसंरचना, संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, कम आय के प्रभाव से अशिक्षा, कुपोषण घरेलू हिंसा, अपराध, बालश्रम, बीमारियां आदि अनेक समस्याओं से ही जूझते हुए देश के संपोषित विकास की राह एवं लक्ष्य प्राप्ति अत्यधिक कठिन है।

(ब) मूलभूत सुविधाओं (बिजली–पानी–भोजन) का अभावः भारत की लगभग आधे से अधिक जनसंख्या बेरोजगारी एवं भुखमरी से जूझ रही है। साथ ही स्वच्छ जल एवं बिजली की कमी सर्वत्र व्याप्त है। भारत में स्थायी विकास हेतु इन तीनों की समस्याओं को दूर करने हेतु योजनाबद्ध रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिजली–पानी–भोजन ये तीनों ही आवश्यकताएं एक दूसरे से अन्तर्संबंधित है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या आज भी बदहाली से गुजर रही है और सुविधाओं, संसाधनों एवं आय के पर्याप्त साधनो की कमी से अस्वच्छता, अशिक्षा, अज्ञानता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन–यापन कर रही है। अपनी इन समस्याओं से जूझते हुए ग्रामीण जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में पलायन के लिए विवश हो जाती है। आज शहरी क्षेत्रों के विकास में ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन भी एक बड़ी समस्या या चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है। क्योंकि शहरों के सीमित संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव अनेक समस्याओं को जन्म देता है। इनमें मुख्यरूप से आवास क्षेत्रों की कमी पानी, बिजली एवं मूलभूत साधनों का अभाव आदि समस्याएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एवं खपत अपेक्षाकृत अधिक होगा।

भारत की जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक है। स्वास्थ सुविधाओं का विस्तार नवीन तकनीकों के विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य की अवधारणा ने मृत्युदर को स्थिर करते हुए जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की है। बढ़ती हुई जनसंख्या का देश के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा है और अधिक से अधिक दोहन इन संसाधनों की कमी एवं समाप्ति की ओर संकेत करती है, जो अत्यधिक चिंताजनक है।

(स) तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरणः भारत में पूर्व के कुछ सालों में तीव्र नगरीकरण हुआ है जो कि 2004 में 28.9 प्रतिशत से एक दशक बाद बढ़कर 2013 में 32 प्रतिशत हो गया। लगभग 300 मिलियन जनसंख्या शहरों एवं कस्बों में निवास करती है। शहरों में जनसंख्या की इतनी तीव्र वृद्धि नगरीय संसाधनों को प्रभावित करती है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। गंदी बस्तियों की तीव्र वृद्धि हो रही है। अस्वच्छ पर्यावरण के फलस्वरूप विभिन्न रोगों, गंदगी, अपराधिक प्रवृत्तियों जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार भारत के आर्थिक विकास में औद्योगिकीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु औद्योगिकी विकास से पर्यावरण, मानवीय स्वास्थ्य जल एवं वायु पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, जो अत्यधिक चिंतनीय विषय है।

2. पारिस्थितिकीय क्षरण एवं जैव विविधता का ह्रासः भारत ही विश्व का ऐसा देश है जिसमें विश्व का सर्वाधिक 8 प्रतिशत जैव विविधता एवं 4 पारिस्थितिकीय तंत्र क्षेत्र है। वनस्पतियों की सर्वाधिक प्रजातियां है। इसके पश्चात् भी सुविधाओं/स्त्रोतो की कमी, भुमि क्षरण, जल की कमी असामान्य ढंग से कृषि आदि ऐसी स्थितियां हैं जिससे अवन्यीकरण, सूखा तथा भूमि क्षरण की समस्या गंभीर रूप ले रही है।

3. जलवायु परिवर्तन प्रभाव एवं प्राकृतिक आपदाएंः जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाएं स्थायी विकास की मुख्य चुनौतियां है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक पारिस्थिकीय तंत्र को प्रभावित करता है जो कि भारत की कृषि व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। बाढ़, सूखा, तूफान, जैसी आपदाएं भारत में पानी एवं खाद्यान की समस्याएं उत्पन्न करती है। साथ ही कृषि आधारित जीविका, उद्योग, उत्पादन आदि सभी इससे प्रभावित होते हैं जो कि भारत में स्थायी विकास के अवरोधक तत्व के रूप में दृष्टिगोचर है।

भारत का स्थायी/संपोषित विकास संबंधी एजेण्डा

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (MDG) मुख्य रूप विकासशील देशों द्वारा तय किए गए लक्ष्य है। जिनके आधा पर इन देशों का विकासात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। भारत ने भी अपने स्थायी विकास की चुनौतियों एवं मुद्दों के आधार पर रणनीति एवं योजनाएं तैयार की ताकि MDGs के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। जो कि निम्न प्रकार है :–

1. भारत ने गरीबी निर्मूलन को अपनी विकासात्मक चुनौती के रूप में लिया Rio+20 द्वारा गरीबी को गंभीर वैश्विक चुनौती माना गया है।
2. रोजगार सृजन अजीविका के साधन एवं सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना।
3. जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे पर कार्ययोजना।
4. ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ाना।
5. जेन्डर आधारित समानता व सशक्तिकरण में वृद्धि करना तथा महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक सहभागिता व निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।
6. विकासशील देशों की मुख्य प्राथमिकता शिक्षा को बढ़ावा देना है भारत में भी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही व्यवसायिक, तकनीकी शिक्षा को रोजगार सृजन हेतु बढ़ावा दिया जा रहा है।
7. स्वच्छ जल तथा व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता तथा जल प्रबंधन विकास का प्राथमिक एवं मुख्य मुद्दा है।
8. सबके लिए स्वास्थ्य की अवधारणा के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं एवं नवीन तकनीकी का विकास, जन्म दर को स्थिर करना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है।
9. खाद्यान्न सुरक्षा एक आधारभूत आवश्यकता है, जिसे भारत ने अपने स्थायी विकास में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य में सम्मिलित किया है।

निष्कर्ष

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र ने अपने स्थायी/संपोषित विकास हेतु अनेक चुनौतियों एवं मुद्दों को अपनी कार्य योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों में शामिल किया है। परन्तु स्थायी एवं संपोषित विकास हेतु वर्तमान विकास योजनाओं में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो ही वरन भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त साधन एवं संसाधन उपलब्ध हो सके। साथ ही आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ऊर्जा, खाद्यान्न सुरक्षा, जल आदि के उपभोग में प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता, वन्य, पारिस्थिकीय तंत्र आदि को क्षति न पहुंचे और न ही इनका क्षरण हो। साथ ही इनके संरक्षण एवं संवर्धन को भी प्राथमिक एवं मुख्य मुद्दों के रूप में शामिल किये जाए। पारम्परिक ऊर्जा के संसाधनों के दोहन की अपेक्षा गैर पारम्परिक अथवा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग एवं उपभोग पर जोर दिया जाना आवश्यक है। जीवाश्म कृषि, जल संरक्षण, वन संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण एवं घटते संसाधन आज वैश्विक स्तर पर गंभीर समस्या एवं चिन्ता का विषय है। अतः इन समस्याओं से दूर करने के लिए स्थायी या संपोषित विकास सबसे बड़ी आवश्यकता है ताकि भविष्य की पीढ़ीयों के लिए प्रदूषण रहित पर्यावरण, जैव विविधता, स्वच्छ जल व प्राकृतिक संसाधनों का भंडार उपलब्ध हो।

संदर्भ सूची

1. यू.एन.एफ.सी.सी., 1993, रिपोर्ट।
2. ''रिपोर्ट ऑफ दी नेशनल कमिशन टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ द कॉन्सीट्यूशन'' 2002।
3. यूनाइटेड नेशनस्, 2013, ''नेशनल कन्सलटेशन रिपोर्ट पोस्ट 2015 डेवलपमेन्ट फ्रेमवर्क'' इंडिया।
4. साउथ एशिया एन्वायरमेन्टल आउटलुक, 2009, UNEP
5. द वर्ल्ड बैंक, 2013, रिपोर्ट।
6. दी प्लानिंग कमिशन, द चेलेन्जेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इण्डिया, दी प्लानिंग कमिशन अप्रोच टू द 12 प्लान।
7. टी.ई.आर.आई., 2009, टेरी एनर्जी डाटा डायरेक्टरी एण्ड इयर बुक, न्यू देल्ही इण्डिया।
8. एम.ई.एफ., गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, 2011 ''सस्टनेबल डेवलपमेन्ट इन इण्डिया : स्टॉकटेकिंग इन द रन अप टू रियो+20।
9. ओड़ एल.के., शैक्षिक प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (राजस्थान), (1991)
10. आयोजना, भारत–2006, पृष्ठ–635
11. श्रोत्रिय निरंजन, ''उच्च शिक्षा निम्न स्तर'', आलेख, जनसत्ता–दैनिक, नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसंबर 2007, पृष्ठ 06
12. त्यागी गुरूसरनदास, भारतीय शिक्षा का परिदृश्य, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा (उ.प्र.) 2007, पृष्ठ 316–320